(c) what action Govt. propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (c) The Government are aware of the news report in question. Neither the State Government nor the Central Government have expressed any such views.

ऐसे क्षेत्रों का पता लगाया जाना जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अधिक अतयाचार होते हैं

2874. **श्री रामसिंह राठवा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जहां पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अधिक अत्याचार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में उन क्षेत्रों में पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰एम॰ सईद): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के दृष्टिकोण से पहचाने गए संवेदनशील जिलों/क्षेत्रों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। (नीचे देखिए)।

(ग) भारत सरकार ने, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए किए जाने वाले निवारात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास संबंधी उपायों का ब्यौरा देते हुए, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। विधायी व्यवस्था को भी कठोर बनाया गया है। साथ ही, "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की" रोकथाम) अधिनियम, 1989" के प्रावधानों के प्रभावशील क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों को, समानुपात के आधार पर केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में, 1993-94 के दौरान बजट में 650 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

विवरण

अनुसूचित जातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों के दृष्टिकोण से "संवेदनशील" के रूप में पहचाने गए विभिन्न राज्यों में स्थित जिलों के नाम

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	"संवेदनशील" के रूप में पहचाने गए जिलों के नाम
1.	बिहार	पटना, नालन्दा, रोहतास, भोजपुर, गया, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर और रांची
2.	गुजरात	अहमदाबाद ग्रामीण, मेहसाणा, सुरेन्द्र नगर, जूनागढ़, खेड़ा, अमरेली, राजकोट ग्रामीण, बनासकांठा, बड़ोदरा ग्रामीण, भच और कच्छ
3.	हरियाणा	अम्बाला, करनाल, सोनीपत, गुड़गांव और फरीदाबाद
4.	कर्नाटक	बंगलौर, बीजापुर, कोलार, मैसूर, तुमकुर, गुलबर्गा, बेलगाम, बीदर, चित्रदुर्ग और रायचूर
5.	मध्य प्रदेश	मुरैना, बिलासपुर, पन्ना, रायपुर, जबलपुर, उज्जैन और भोपाल
6.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद, बीड़, उस्मानाबाद, नांदेड़, परभड़ी और बुल्डाना
7.	पंजाब	फिरोजपुर जिला, संगरूर जिला और पटियाला जिला

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	"संवेदनशील" के रूप में पहचाने गए जिलों के नाम
8.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, गोण्डा, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फतेहगढ़, इटावा, बांदा, जालौन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, बदायूं, मेरठ, वाराणसी और आगरा
9.	तमिलनाडु	दक्षिण आर्कोट जिला, त्रिची, तंजावूर, मदुराई, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली कट्टाबोमम्मन, कामराजार, चिदम्बरानार और तिरुवनामलाई सम्बुवरायार

Privileges to Kodavas Community

2875. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether it is a fact that Kodavas community of Coorg in Karnataka has been enjoying some privileges under Indian Arms Act since preindependence era;

(b) Whether it is also a fact that Govt. propose to withdraw these privileges and if so, what are the reasons therefore; and

(c) Whether Government propose to maintain status quo in this respect and if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The status quo is being maintained for the present.

Released of Militants in J&K without Screening

2876. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) The number of militants released by the Jammu and Kashmir Police without screening after their surrender;

(b) The number of militants still in the custody of Jammu and Kashmir Police;

(c) Whether any criteria has been fixed in determining the release of these militants and if so, the details thereof;

(d) Whether the criteria has the approval of the Central Government?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI RAJESH PILOT): (a) to (d) The Jammu & Kashmir Government have not released any militants without screening after the surrender. Out of the 62 persons who came out of Hazratbal Shrine at the time of the surrender, 35 persons found to be innocent on screeing were released initially. Of the remaining 27 persons, 23 have been released on bail pursuant to orders of the competent Court on different dates between 27 November and 6th December. The criteria followed by the State Government was that those who were found to be innocent would be released forthwith while the remaining persons would be subjected to the due process of law.

Illegal Detention by Delhi Police

2877. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether any cases of illegal detention of the so called accused person/ persons by Rajouri Garden West District Police in Delhi on 10th September, 1993 without obtaining Magisterial orders have come to the notice of Government;

(b) What are the criteria adopted by the Police whenever they take into custody somebody under section 406 and 498A of CPC;

(c) What is the stipulated time taken by police to produce the accused before a magistrate under sections mentioned in part (a);

(d) What is the time taken by the police to inform the concerned Government Departments where such persons are working in Central Government;